

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

इ0पी0न0-3-10

क्रमांक-137/2017

आरबीई सं0-53/2017

सं0 ई/ 9/2 भाग - पांच / चर

दिनांक 11-07-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- पाँच वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति पर, प्रतिनियुक्ति (डियूटी) भत्ते की स्वीकार्यता।

10812 रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2010/एफ (ई) 11/1(1) दिनांक 19.06.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

[Signature]
(ए0 के0 सिंह)
11.07.17

उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्या/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

[Signature]
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक
11.07.17

[Signature]
7-2017

CPO

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

महाप्रबन्धक कार्यालय
दूरिंतर स्तरी, नई दिल्ली
20 JUN 2017
PB
महाप्रबन्धक 3

F.No.2010/F(E)II/1(1)/1

RBE No. 58/2017
New Delhi, dt. 19.06.2017

AM/ M. ER
The General Managers/FA&CAOs,
All Indian Railways & Production Units incl. RDSO,
(As per Standard Mailing List)

Sub:- Admissibility of Deputation (Duty) Allowance while on deputation-
beyond 5th year.

Consolidated guidelines on 'Deputation' have been issued by DOP&T vide their O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17.06.2010 & No. 2/6/2016-Estt.(Pay-II) dated 17.02.2016 which have been adopted/circulated on the Railways vide Board's letter dated 28.07.2010 & 21.04.2016 respectively.

2. Further, DOP&T in the context of their O.M No. 2/6/2016-Estt.(Pay-II) dated 17.02.2016 (wherein, powers were delegated to Ministries/Deptt./Borrowing organisations to extend deputation tenure upto a period not exceeding seven (7) years at a stretch) have reiterated vide their O.M. No. 2/6/2016-Estt.(Pay-II) dated 23.02.2017 that deputation (duty) allowance is admissible only upto the fifth year, if the deputationist has opted to draw deputation (duty) allowance.

3. A copy of these instructions is sent herewith for information/guidance. These will apply mutatis-mutandis to Railway employees also.

4. Please acknowledge receipt.

DA: As above.

F.No.2010/F(E)II/1(1)/1

(Amir Chand Jain)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board.

New Delhi, dt. 19.06.2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan.

For Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

का.सं.2010/एफ(ई)II/1(1)/1

आरबीई सं. 58/2017
नई दिल्ली, दि.19.06.2017

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं अ अ मा सं सहित उत्पादन इकाइयां
(नमक डाक सूची के अनुसार)

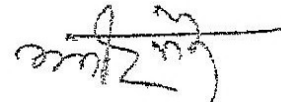
विषय:- पाँच वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की स्वीकार्यता।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं.6/8/2009-ईस्ट.(पे-II) एवं दिनांक 17.02.2016 के सं.2/6/2016-ईस्ट.(पे-II) के तहत 'प्रतिनियुक्ति' के संबंध में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें बोर्ड के क्रमशः दिनांक 28.07.2010 और 21.04.2016 के पत्र के तहत सभी रेलों में लागू/परिपत्रित किया गया है।

2. इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 17.02.2016 के का.जा. सं.2/6/2016-ईस्ट.(पे-II) (जिसमें प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को लगातार अधिकतम सात (7) वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/विभागों/उधार लेने वाले संगठनों को शक्तियाँ दी गई थी) के संदर्भ में उन्होंने दिनांक 23.02.2017 के अपने का.जा. सं.2/6/2016-ईस्ट.(पे-II) में यह दोहराया कि यदि प्रतिनियुक्ति पदधारी ने प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता लेने का चयन किया है, तो प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता केवल पाँच वर्ष तक ही स्वीकार्य होगा।

3. इन अनुदेशों की एक प्रति आपकी सूचना/मार्गदर्शन हेतु भेजी जाती है। ये यथोचित परिवर्तनों सहित रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

4. कृपया पावती दें।



(अमीर चंद जैन)

उप निदेशक वित्त (स्था.)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

का.सं.2010/एफ(ई)II/1(1)/1

नई दिल्ली, दि.19.06.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं.224 रेल भवन को प्रेषित।



कृते वित्त अ.पु.क. सं. 1/2017

No. 2/6/2016-Estt.(Pay-II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi
Dated: 23rd February 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Admissibility of Deputation (Duty) Allowance while on deputation - regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 17th February 2016 vide which powers were delegated to Ministries / Departments / borrowing organisations to extend deputation tenures up to a period not exceeding 7 years at a stretch, in respect of cases covered by the O.M. dated 17th June 2010.

2. The matter regarding the admissibility of Deputation (Duty) Allowance in view of the change in maximum number of years of deputation tenure as provided above has been examined in this Department.

3. As per Para 8.3.2 of the OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17th June 2010, where the extension is granted up to the fifth year, the official concerned will continue to be allowed Deputation (Duty) Allowance, if he/she has opted to draw deputation (duty) allowance.

4. This Department's O.M. No. 2/6/2016-Estt.(Pay-II) dated 17th February 2016 delegates powers to Ministries / Departments / borrowing organisations, to extend deputation tenures up to a period of 7 years in a stretch, in respect of cases covered by the O.M. dated 17th June 2010. However, there has been no modification of the Para 8.3.2. of the O.M. dated 17th June 2010 by the O.M. dated 17th February 2016. The new O.M. dated 17th February 2016 provides vide Para 4 that all other terms and conditions issued vide OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17th June 2010 will remain unchanged.

5. Thus, admissibility of Deputation (Duty) Allowance would be only as per Para 8.3.2 of the O.M. dated 17th June 2010, i.e. only up to the fifth year, if the deputationist has opted to draw Deputation (Duty) Allowance.



(A.K. Jain)

Deputy Secretary to the Government of India
2011-2309 4542

To

✓ All Ministries / Departments of the Government of India (As per standard list)

Copy to:

NIC, DoPT - to upload the O.M. on the Department's website under "What's new" and also under "Establishment" sub-head "Deputation"